अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ बृहस्पतिवार, 13 अप्रैल 2023

"सहनशील होना अच्छी बात है, पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है।
- जयशंकर प्रसाद

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के करीब सवा साल बाद वहां की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा की भारत यात्रा कूटनीतिक रुप से तो महत्वपूर्ण है ही, इस चुनौतीपूर्ण समय में जी-20 के अध्यक्ष के रुप में भारत से यूक्रेन संतुलनकारी भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा है, तो यह भी स्वाभाविक है।

यूक्रेन से रिश्ते

यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा की भारत यात्रा सिर्फ इस अर्थ में उल्लेखनीय नहीं है कि पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद, जिसे रूस ने 'विशेष कार्रवाई' का नाम दिया है, वहां के किसी मंत्री का यह पहला भारत दौरा है, बल्कि पिछले एक साल में भारत और यूक्रेन के रिश्ते को देखते हुए भी इस यात्रा को कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानना चाहिए। यूक्रेन पर हमले की निंदा करने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर वोटिंग के दौरान भारत लगातार अनुपस्थित रहा है, रूसी आक्रामकता की प्रतिक्रिया में यूरोपीय देशों द्वारा उसके कच्चे तेल का बहिष्कार करने की स्थिति में भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, जिस पर न केवल अनेक देशों की आपत्ति रही है, बल्कि यूक्रेन के विदेश मंत्री पिछले साल यह तक कह चुके हैं कि भारत यूक्रेन के लोगों का खून खरीद रहा है। और तो और, विगत जुलाई में जिन देशों के रवैये पर क्षुब्ध होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था, उसमें भारत स्थित यूक्रेन के राजदूत भी थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की मजबूत वैश्विक छवि और संतुलनकारी रवैये से स्थिति लगातार बेहतर बनती गई। यह ठीक है कि रूस से भारत के आजमाए हुए रिश्ते हैं, इसके बावजूद युद्ध छिड़ने के बाद से भारत यूक्रेन की सरकार से संपर्क में है, उसने रूस के रुख पर चिंता जताते हुए संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र और राष्ट्रों की संप्रभुता को महत्वपूर्ण बताया है। पुतिन से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोटूक यह भी कह चुके हैं कि यह दौर युद्ध का नहीं है। ऐसे ही, भारत को इस साल जी-20 की अध्यक्षता मिलने के बाद यूक्रेन का रुख बदला है। इसी के तहत यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री ने भारत आकर दोतरफा रिश्तों को मजबूत बनाने की बात कही और आगामी सितंबर में होने वाली जी-20 की शिखर बैठक में राष्ट्रपति जेलेंस्की को आमंत्रित करने का प्रस्ताव रख भारत को असमंजस में भी डाल दिया।

पिछले साल हुई जी-20 की शिखर बैठक को भी जेलेंस्की ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया था। कुल मिलाकर, इस चुनौतीपूर्ण समय में जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत से जिम्मेदारी भरी और संतुलनकारी भूमिका निभाने की उम्मीद यूक्रेन समेत पूरा विश्व कर रहा है, तो यह बहुत स्वाभाविक है।

वित्तीय समावेशन और महिलाएं

भारत में लघु वित्तीय कंपनियों ने उन गरीब, कामगार व ग्रामीण महिलाओं के साथ भरोसे का रिश्ता बनाया है, जो लंबे समय तक बैंकिंग व्यवस्था के बाहर थीं। इस उद्योग को अब ऐसी रणनीति पर काम करना चाहिए, जो कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाए।

कमजोर महिलाओं के समूह को बगैर किसी कोलैटरल (एक ऐसी संपत्ति जिसे ऋण देने वाला ऋण की सुरक्षा के तौर पर स्वीकार करता है) के लघु वित्त मुहैया कराने की प्रवृत्ति भारत से जुड़ी आर्थिक खबरों में अब भी महत्व रखती है। लघु वित्त के इस क्षेत्र में घरेलू तथा वैश्विक, दोनों स्रोतों से नए निवेश आते रहते हैं। इन निवेशों के जरिये ही भारत की दर्जनों लघु वित्तीय कंपनियां (एमएफआई) हाशिये के समूहों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करती हैं, और जो इन कंपनियों के लिए अब भी एक आकर्षक उद्यम बना हुआ है। एक दशक पहले तक भारत का लघु वित्तीय क्षेत्र मीडिया के निशाने पर था। मसलन, आंध्र प्रदेश में मीडिया संस्थानों ने कर्ज वसूली के हिंसक तरीकों और नतीजतन कर्ज लेने वालों की आत्महत्याओं का जिक्र करते हुए लघु वित्तीय कंपनियों पर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन अब इस मामले में मीडिया का फोकस कर्ज लेने वालों की मुश्किलों के बजाय दूसरे मुद्दों पर है। इसके बावजूद गरीब महिलाओं पर ध्यान देने के कारण लघु वित्तीय कंपनियां अब भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या ये कंपनियां जरूरतमंद महिलाओं को वह मदद और सेवाएं मुहैया कराती हैं, जिनकी इन्हें जरूरत है? और ऐसा क्यों है कि ऐसा उद्योग जिसका ध्यान सिर्फ शेयरधारकों के मुनाफे पर है, कमजोर समूहों की महिलाओं को भारत की वित्तीय पारिस्थितिकी से बाहर रखता है?

स्मिता राधाकृष्णन

अपनी हालिया किताब में, जो भारत के व्यावसायिक लघु वित्त क्षेत्र पर मेरे एक दशक के शोध का नतीजा है, मैंने यह दिखाया है कि भारत का लघु वित्त उद्योग न केवल हाशिये की महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाने के अपने लक्ष्य से चुक गया है, बल्कि लघु वित्तीय कंपनियों की रणनीति में शायद ही कभी कमजोर महिलाओं की जरूरतों की चिंता होती है। इसके विपरीत इस उद्योग के दैनंदिन क्रियाकलापों में लैंगिक विषमता का प्रमाण इनके संस्थानों की कार्यसंस्कृति से लेकर ग्राहकों-कर्ज लेने वालों से इनकी बातचीत तक में स्पष्ट होता है।

यह उद्योग कर्ज लेने वाली गरीब महिलाओं से काम कराता है, पर उसका मेहनताना नहीं देता। ये महिलाएं समूह गठित कर तथा व्यक्तिगत जानकारियों और श्रम के जरिये इन कंपनियों की कर्ज वसूली में मदद करती हैं। मसलन, बंगलूरू में मैं एक ऐसी महिला नेत्री से मिली, जो अपने पड़ोसियों की मदद करने का दावा कर रही थी। उनसे और उनके समूह की दूसरी महिलाओं से विस्तार से बातचीत करने के बाद स्पष्ट हुआ कि अपने रसूख का इस्तेमाल कर वह अपने समुदाय की महिलाओं का ऐसा समूह तैयार करती हैं, जो लघु वित्तीय कंपनी के हित में हो। ऐसे समूहों में गरीब महिलाएं भी शामिल होती हैं और तुलनात्मक रूप से संपन्न महिलाएं भी, इनमें उद्यमी, किरायेदार और घर का काम करने वाली-सभी तरह की महिलाओं को शामिल किया जाता है।

लघु वित्तीय कंपनियों की साख के लिए यह आवश्यक है कि वे अलग-अलग तरह के समूह तैयार करें। लेकिन अब तक इन कंपनियों के कर्मचारी ऐसा कर पाने में विफल रहे हैं। ऐसे में, वे ऐसी महिलाओं की मदद लेती हैं, जिनका अपने समुदाय में दबदबा होता है। मैं जिस महिला नेत्री का जिक्र कर रहा था, उसने प्यार और दबाव से अलग-अलग श्रेणी की महिलाओं को जोड़कर उन्हें एक साथ लघु वित्तीय कंपनी से कर्ज लेने के लिए कहा, लेकिन बातचीत में वह दावा कर रही थीं कि यह काम वह महिलाओं की सेवा के लिए करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे काम के पीछे उस महिला नेत्री के अपने स्वार्थ भी रहे होंगे, लेकिन यह तय है कि इस काम के लिए कंपनी उन्हें कोई पैसा नहीं देती।

लघु वित्त क्षेत्र की बेहद सकारात्मक छवि है। माना जाता है कि यह उद्योग महिलाओं को लघु उद्यमी व आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण काम करता है। पर भारत में कर्ज लेने वाली ऐसी महिलाएं उद्यमी नहीं बनतीं। बल्कि छोटा-मोटा कर्ज वे स्कूल की फीस देने, जरूरी चिकित्सा खर्च और महंगा कर्ज चुकाने के लिए लेती हैं। लघु वित्तीय कंपनियों को इससे फायदा होता है। छोटे कर्ज चुकाने के दरम्यान कर्ज लेने वाले एक वर्ष बाद ज्यादा बड़ा कर्ज ले सकते हैं, जिससे लघु वित्तीय कंपनियों का मुनाफा भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है।

लघु वित्तीय कंपनियों की जो कार्यसंस्कृति है, उसमें महिला कर्मचारियों को आगे बढ़ने के अवसर पुरुष कर्मचारियों की तुलना में कम मिलते हैं। एक महिला कर्मचारी ने मुझे बताया कि महिलाओं के एक समूह द्वारा कर्ज लेने के बाद उसकी नेत्री भाग गई, ऐसे में, दूसरी महिलाओं द्वारा अपने कर्ज के साथ उसका कर्ज भी चुकाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में, उस महिला कर्मचारी ने फरार नेत्री के घर का दरवाजा तोड़ उसका सामान निकाल कर बेच देने के लिए कहा। ऐसा वह न कहती, तो खुद उस महिला कर्मचारी का रिपोर्ट कार्ड खराब हो जाता, क्योंकि उस समूह को कर्ज उसी ने दिलवाया था। लघु वित्तीय कंपनियों से कर्ज लेने वाली महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे अनिवार्यतः गरीब ही हों। विजया नाम की एक महिला को अपने गर्भाशय के ऑपरेशन के लिए जब पैसों की जरूरत थी, तब उसके समुदाय की एक प्रभावशाली महिला ने एक लघु वित्तीय कंपनी से कर्ज दिलवाया। विजया अपनी परिचित महिला के साथ-साथ उस कंपनी के प्रति भी कृतज्ञ थी, क्योंकि उसने जो ब्याज लिया, वह उसके पड़ोस के महाजन द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम था। इस अर्थ में विजया जैसी महिलाओं के लिए लघु वित्तीय कंपनियों का महत्व निश्चय ही ज्यादा है, लेकिन विडंबना यह है कि महिला समूहों को कर्ज देने वाली इन कंपनियों की रणनीति में महिला सशक्तीकरण कभी नहीं होता।

चूंकि ये कंपनियां बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को कर्ज देती हैं, जिनमें महिला समूहों की संख्या बहुत अधिक है, ऐसे में, इन्हें ऐसी रणनीति पर काम करना चाहिए, जो देश की कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाएं। इसमें कोई शक नहीं कि लघु वित्तीय कंपनियों ने गरीब, कामगार और ग्रामीण महिलाओं के साथ, जो लंबे समय तक बैंकिंग व्यवस्था के बाहर थीं, भरोसे का रिश्ता बनाया है। ऐसे में, समय आ गया है कि यह उद्योग जरूरतमंद महिलाओं की बड़ी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में भी काम करे।

-लेखिका अमेरिका के वेलेस्ले कॉलेज में प्रोफेसर हैं।

edit@amarujala.com

प्यारे लाल कुरील
(1916-1984)

आजादी के अमृत कथन

ये तमाम बंजर जमीन यदि काश्त में आ जाएगी, तो इससे हमारी पैदावार काफी बढ़ जाएगी और जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं, उन्हें खेती करने का जरिया मिल जाएगा।

बिचौलियों को खत्म कर कीमतों पर नियंत्रण जरूरी

महोदया, हिंदुस्तान के अंदर एक तबका ऐसा है, जिसको खेतिहर मजदूर कहा जा सकता है और जिनके पास जमीन नहीं है। दो सौ लाख एकड़ बंजर भूमि बिल्कुल परती पड़ी हुई है और हमारे मुल्क में बीस फीसदी खेतिहर मजदूर ऐसे हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है। योजना आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, यह जो खेतिहर मजदूर हैं, उनका कोई जरिया-ए-आमदनी नहीं है। उनमें से 16 फीसदी घर दो सौ रुपये सालाना कमाते हैं, जिनमें ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। उसी से वे अपना गुजारा करते हैं। बहुत से लोग सवाल करेंगे कि आखिर वे गुजारा कैसे करते हैं? चोरी करते हैं, भीख मांगकर गुजारा करते हैं और दूसरे लोगों के यहां बेगारी करके थोड़ा-बहुत जो खाने को मिल जाता है, उसी से वे गुजर-बसर करते हैं। उनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए इस बंजर जमीन को केंद्रीय विषय बना दिया जाए, चाहे उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़े, क्योंकि हम देखते हैं कि राज्य सरकारें इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं और राज्य सरकारों की लापरवाही की वजह से ये तमाम बंजर भूमि बगैर खेती के पड़ी हुई है। खेतिहर मजदूर इस जमीन के जरिये पैदावार में भारी इजाफा कर सकते हैं। इसलिए ये सारी जमीन उनको दे दी जाए। ये तमाम बंजर जमीन यदि काश्त में आ जाएगी, तो इससे हमारी पैदावार काफी बढ़ जाएगी और जो हमारे खेतिहर मजदूर हैं, उन्हें खेती करने का जरिया मिल जाएगा।

समाज के अंदर से बिचौलियों को निकाल कर ऐसा निजाम बनाया जाए और इस तरह से दामों पर नियंत्रण किया जाए कि किसान को जब अनाज फिर से खरीदना पड़े, तो डेढ़ गुना से ज्यादा उसको पैसा न देना पड़े।

इसके बाद किसान हैं, जो अपने खेत से पैदावार करते हैं और उसे हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनके साथ कितनी बेइंसाफी होती है कि जब फसल होती है, तो तमाम बिचौलिए और छोटे-छोटे व्यापारी आते हैं और वे इन किसानों से अनाज सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। उन्हें जिंदगी की दूसरी जरूरतों के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वे मजबूरी में अपना अनाज सस्ते दामों पर बिचौलियों को दे देते हैं। पर कुछ समय बाद जब उन्हें खुद अनाज की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें दो-तीन गुना ज्यादा दाम देकर वही अनाज खरीदना पड़ता है। इसके लिए समाज के अंदर से बिचौलियों को निकाल कर ऐसा निजाम बनाया जाए और दामों पर इस तरह से नियंत्रण किया जाए कि किसान को जब अनाज फिर से खरीदना पड़े, तो डेढ़ गुना से ज्यादा उसको पैसा न देना पड़े। यह बहुत जरूरी चीज है और जब ऐसा होगा, तभी किसान की हालत बेहतर बन सकती है।

इसी तरह से मजदूर हैं कारखाने के। उनकी मजदूरी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जो मिल मालिक हैं, उनके लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि वे अपने मुनाफे में मजदूरों को हिस्सा दें। अगर सार्वजनिक के साथ-साथ निजी क्षेत्र को आप कायम रखना चाहते हैं, तो आप मुनाफे में से उन मजदूरों को भी हिस्सा दें। जब उनका मुनाफे में हिस्सा होगा, तो उत्पादन भी ज्यादा होगा और आपके लिए उनके दिलों में इज्जत होगी और आपका काम और आगे बढ़ेगा। जब तक सरकार चीजों की कीमतों पर और खास तौर से खाने-पीने की चीजों पर नियंत्रण नहीं करती है, गरीब आदमी उन चीजों को खरीद नहीं सकता। इसलिए मेरा कहना है कि बिचौलियों को आप खत्म कर दीजिए और जरूरत की चीजों के दाम मुकर्रर कर दीजिए और उसके बाद उसके वितरण का सही तरीका इस्तेमाल कीजिए।

-राजनेता व सांसद के 13 सितंबर, 1963 को राज्यसभा में दिए भाषण के संपादित अंश।

दूसरा पहलू

आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है कि ग्रीनहाउस गैसों के रिकॉर्ड उत्सर्जन के लिए इंसान ही जिम्मेदार है।

घटाना होगा तापमान, तभी बचेंगे हम

जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया गहरे संकट में है। लेकिन अगर हम वाकई इससे निपटने का बीड़ा उठा लें, तो चीजें बदल सकती हैं। आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है कि ग्रीनहाउस गैसों के रिकॉर्ड उत्सर्जन के लिए इंसान ही जिम्मेदार है। अभी वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जिसके 2030 के दशक में डेढ़ डिग्री तक पहुंच जाने की आशंका है। इस बढ़ते तापमान की वजह से दुनिया में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिनमें समुद्र स्तर बढ़ना और तेज जलवायु बदलाव जैसी घटनाएं शामिल हैं। इससे लोगों की जान, आजीविका और प्राकृतिक व्यवस्था को व्यापक नुकसान हो रहा है। विकासशील देशों के लोग, जिनकी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कम भागीदारी है, जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और इसका असर कई पीढ़ियों पर पड़ता है।

फ्रैंक जोत्जो

विकासशील देशों के लोग, जिनकी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कम भागीदारी है, वे जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और इसका असर कई पीढ़ियों पर पड़ता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी नीतियां बनें, जो राजनीतिक रुप से स्वीकार्य हों और गरीबों को भी कोई नुकसान न पहुंचे। इसके लिए शोध और विकास पर ज्यादा निवेश करना होगा।

इस रिपोर्ट का सार यह है कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन और इनकी तीव्रता इस वक्त रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर दो डिग्री के भीतर रखने के लिए ग्रीनहाउस गैसों के वैश्विक उत्सर्जन में 2030 तक 21 फीसदी और 2035 तक 35 फीसदी की कमी लाना जरूरी है। तापमान को डेढ़ डिग्री से कम रखने के लिए उत्सर्जन में ज्यादा कटौती की जरूरत है। पर उत्सर्जन को देखते हुए तापमान में कमी लाना भारी चुनौती है। हालांकि उत्सर्जन घटाने में सफलता भी प्रमाणित हो चुकी है। आईपीसीसी का कहना है कि मौजूदा नीतियां, कानून, प्रौद्योगिकी और दुनिया भर के प्रयासों के चलते कई अरब टन ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में पहले ही कटौती हो चुकी है, वर्ना हालात कुछ और ही होते। अगर मौजूदा नीतियों को व्यापक रूप से लागू किया जाए, तो वैश्विक उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। यदि सभी उपलब्ध तकनीकी विकल्पों का उपयोग किया जाए, तो 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन आधा तो किया ही जा सकता है, वह भी उचित लागत में।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी नीतियां बनें, जो राजनीतिक रूप से स्वीकार्य हों और गरीबों को भी कोई नुकसान न पहुंचे। जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों के लिए अच्छे संस्थानों की स्थापना हो और इनमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए शोध और विकास पर ज्यादा निवेश करना होगा और लंबी अवधि की योजनाएं बनानी होंगी। अगर हम उत्सर्जन पर लगाम लगाने में नाकाम रहते हैं, तो बाढ़, सूखा, लू, दावानल और तूफान संबंधी खतरे भी बढ़ेंगे। *(-साथ में मार्क हॉडेन)* *-द कन्वर्सेशन से*

आंकड़े

इंटरनेट का बढ़ता उपयोग

देश में वर्ष 2015 में प्रति 100 लोगों पर इंटरनेट ग्राहक 25.73 थे, जो 2022 में 61 से ज्यादा हो गए।

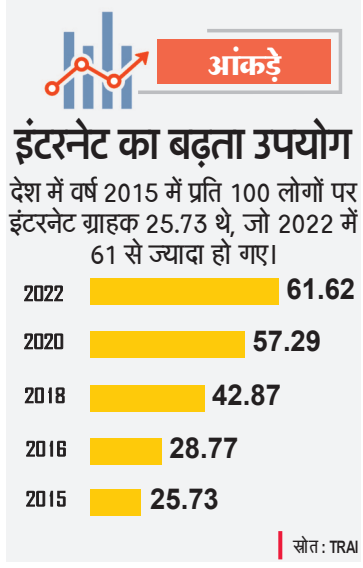

स्रोत : TRAI

एक सच्चे मित्र का धर्म है कि वह अपना दुख भूलकर मित्र का दुख दूर करने में पूर्ण सहयोग दे। कुसंग से बचाकर अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे।

मित्र के लक्षण

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

वनवास के दौरान भगवान श्रीराम सीता जी की खोज करते समय सुग्रीव के संपर्क में आए थे। सुग्रीव अपने अधर्मी भाई बालि के आतंक से पीड़ित थे। बालि ने उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था। श्रीराम ने बालि का वध कर सुग्रीव को राजा बनवाया।

एक दिन सुग्रीव श्रीराम के सत्संग के लिए पहुंचे। श्रीराम ने उन्हें कहा, 'मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र शूल के समान हर समय पीड़ा देते हैं। अतः इनसे विमुख रहने में भलाई है। जो मित्र सामने कोमल और मधुर वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, साथ ही मन में कुटिलता रखता है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है।' वह आगे कहते हैं, 'एक सच्चे मित्र का धर्म यह है कि वह अपना दुख भूलकर मित्र का दुख दूर करने में पूर्ण सहयोग दे। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को कुसंग से बचाकर अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। विपत्ति के समय जो काम नहीं आता, उसे मित्र नहीं मानना चाहिए।' श्रीराम घर-परिवार की महिलाओं को एक समान समझने और उन्हें सम्मान देने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, *अनुज बधू भगिनी, सुत नारी। सुनु सठ, कन्या सम ए चारी॥* अर्थात छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्रवधु और कन्या-इन चारों को एक समान समझना चाहिए।

श्रीराम के प्रेरक उपदेश सुनकर सुग्रीव उनके चरणों में झुक गए। *(अमर उजाला आर्काइव से)*

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 25 अगस्त, 1980

उपद्रवों के खिलाफ दिल्ली में निकाला गया शांति जुलूस

दिल्ली में शांति के लिए शांति जलूस

नई दिल्ली, 24 अगस्त। गांधी शांति प्रतिष्ठान व दिल्ली कांग्रेस (इं) की ओर से आज राजधानी में एक शांति जुलूस निकाला गया। जुलूस में विभिन्न सम्प्रदायों तथा सामाजिक संगठनों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जुलूस का मुख्य उद्देश्य हाल के उपद्रवों के खिलाफ जनता को जाग्रत करना था।

यह शांति जुलूस जो पुरानी दिल्ली स्थित टाउन हाल से शुरू हुआ, चांदनी चौक, लालकुआं, जामा मस्जिद, दरियागंज होता हुआ

गांधी शांति प्रतिष्ठान व दिल्ली कांग्रेस की ओर से राजधानी में एक शांति जुलूस निकाला गया। जुलूस में विभिन्न सम्प्रदायों तथा सामाजिक संगठनों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जुलूस का मुख्य उद्देश्य हाल के उपद्रवों के खिलाफ जनता को जाग्रत करना था।

लोहे को जीवन से जोड़तीं स्त्रियां

कड़ी मेहनत के बावजूद इन महिलाओं की कोई निश्चित दैनिक आय नहीं है। बड़े पैमाने पर मशीनीकरण ने उन्हें लाभ से वंचित कर दिया है।

शेफाली मार्टिन्स

समुदाय

कृषि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। कृषि के लिए औजारों की उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। किसानों को ये औजार लोहार प्रदान करते हैं। लोहार प्राचीन काल से ही लोहे की धातु को अलग-अलग आकार देकर औजार गढ़ते आ रहे हैं। लेकिन गड़िया लोहारों का समुदाय आज भी गुमनामी के अंधेरे में है। वे अपने काम में पारंपरिक ज्ञान के साथ वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करते रहे हैं, वह भी बिना कभी स्कूल गए। इस समुदाय की महिलाएं भी पुरुषों के बराबर इस काम को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी निभा रही हैं।

राजस्थान में अजमेर-जयपुर हाई-वे के किनारे पारसोली गांव में गड़िया लोहारों का एक गांव घोर गरीबी में जीवन-यापन कर रहा है। इसी कस्बे की 60 वर्षीय डाली गड़िया लोहार कहती हैं, 'हमें नहीं पता कि स्कूल कैसा दिखता है? हमने पंद्रह साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। हम अपने माता-पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठकर लोहे का सामान बेचने एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। जमाना बदल गया है, लेकिन हमारे हालात नहीं बदले।' ये लोहार मूल रूप से मेवाड़ के थे और शासकों के लिए हथियार बनाते थे। जब महाराणा प्रताप ने अपना राज्य खो दिया, तो लोहारों ने भी खानाबदोशों की तरह जीने की कसम खाई।

जीवन-यापन के लिए वे सामान बनाकर बैलगाड़ी पर उसे गांव-गांव बेचते रहे। इस बैलगाड़ी की वजह से उन्हें गड़िया लोहार कहा जाने लगा। लोहारों के इस समुदाय में महिलाएं धातु को औजार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुरुष जहां अंगारों को गर्म करके लोहे पर प्रहार करता है, वहीं महिला पहले अंगारों को पंखा करती हैं और फिर पुरुष के साथ मिलकर धातु को आकार देने में मदद करती हैं। यह कड़ी मेहनत और बहुत कठिन प्रक्रिया है। ये महिलाएं बचपन से ही इस काम को सीखती हैं। महिलाएं सामान बनाने के अलावा गांव-गांव, मेला-दर-मेला जाकर भी अपना उत्पाद बेचती हैं। वे चिमटा, छलनी, दांतली (हाथ की आरी), कुल्हाड़ी, हंसिया और कुदाल बनाती हैं। सामान बनाने के लिए लोहा और कोयला शहर से खरीदती हैं।

इनमें से अधिकांश का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पिछले एक दशक से एक ही जगह पर बसने के कारण अब उनके बच्चे पास के एक सरकारी स्कूल में जाते हैं। उनके काम में कई खतरे भी शामिल हैं। न केवल धधकती आग के सामने उन्हें घंटों बैठना पड़ता है, बल्कि औजार बनाने के दौरान चोट लगने की भी काफी आशंका रहती है। कड़ी मेहनत के बावजूद इन महिलाओं की कोई निश्चित दैनिक आय नहीं है। बड़े पैमाने पर मशीनीकरण ने उन्हें लाभ से वंचित कर दिया है। अब मशीन से बने आधुनिक औजार मौजूद हैं, जो बहुत सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। ऐसे में इनके बनाए औजारों को भला कोई क्यों खरीदेगा।

अब वे सड़क किनारे बैठकर ताले, जंजीर, रसोई के चाकू, घंटियां, चम्मच, चूहेदानी आदि बेचती हैं, जिनसे उन्हें बहुत कम मुनाफा होता है। कमला गड़िया लोहार कहती हैं, हम 20,000 रुपये का सामान खरीदते हैं, पर हमारी कुल कमाई सिर्फ 2,000 रुपये होती है। इस मंहगाई के दौर में महीने में दो-तीन हजार रुपये की कमाई से क्या हो सकता है!

संतोष गड़िया लोहार की भी यही कहानी है। वह कहती हैं, 'हम एक सामान से पांच से दस रुपये ही कमाते हैं। हम कुछ सामान खुद बनाते हैं, और कुछ बेचने के लिए बाजार से खरीदते हैं। मशीनीकरण से हमारा पारिवारिक व्यवसाय प्रभावित हुआ है।' मेले हस्तशिल्प के प्रचार-प्रसार के महत्वपूर्ण स्थल हैं, पर इन लोहारों के लिए यह लाभप्रद नहीं है। पुष्कर मेला भी अब इनके लिए लाभदायक नहीं रहा है। मेले के आयोजक उनसे प्रति फुट किराये के रूप मे 3,000 रुपये लेते हैं, फिर उन्हें मेले में स्थायी जगह नहीं मिलती है। सामान बिके या न बिके, किराया तो देना ही पड़ता है। यही कहानी क्षेत्र के दूसरे प्रमुख मेले 'अजमेर शरीफ में उर्स मेले' की है।

गड़िया लोहार समुदाय की ये मेहनती महिलाएं उस दिन का इंतजार कर रही हैं, जब उनके बनाए सामान एक बार फिर से लोकप्रिय होंगे और वे अच्छी कीमत पर बिकने लगेंगे। *(चरखा फीचर)*